बजट की मुख्य विशेषताएं
2026-27
उत्तर प्रदेश सरकार

फरवरी 2026

“माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प हेतु प्रतिबद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट, उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति, युवा वर्ग, अन्नदाता किसान सहित समाज के वंचित एवं गरीब के उत्थान तथा खुशहाली के लिए समर्पित है। विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट निवेश का वातावरण, नारी समृद्धि के लिए अभूतपूर्व प्रयास, युवाओं के लिए अद्वितीय अवसर, कृषकों के लिए अनेक प्रोत्साहन, आधुनिक तकनीक के साथ रोजगार सृजन, बहुआयामी गरीबी से मुक्ति के अभिनव प्रयासों को आत्मसात करने वाला बजट है। इस हेतु माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार व उनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई।”

- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

बजट परिदृश्य

केन्द्रीय बजट के कर्तव्य आधारित ढांचे को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश ने राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए चार मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित किया है।

1

आर्थिक गतिविधियों में तेजी एवं सतत विकास

बुनियादी ढांचे, उद्योग और निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास पथ में तेजी

2

नागरिकों की आकांक्षाओं को वास्तविक स्वरूप देना

बेहतर शिक्षा, कौशल, रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के माध्यम से नागरिकों की आकांक्षाओं को परिणामों में बदलना

3

समावेशी और संतुलित विकास

सामाजिक बुनियादी ढांचे का विस्तार और अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार कर समावेशी एवं क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास सुनिश्चित करना

4

महिला सशक्तीकरण

विजन 2047 की दिशा में महिलाओं के लिए रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी, समावेशी, आत्मनिर्भर और सतत विकास का मुख्य आधार होगा

बजट: मुख्य बिन्दु

(₹ लाख करोड़ में)

बजट के आकार में वृद्धि (₹ लाख करोड़ में)

बजट वित्तीय वर्ष 2026-27

प्राप्तियां	₹ लाख करोड़ में
कुल प्राप्तियां	**8.48**
राजस्व प्राप्तियां	**7.29**
राज्य का स्वयं का कर राजस्व	**3.34**
पूंजीगत प्राप्तियां	**1.19**

व्यय	₹ लाख करोड़ में
कुल व्यय	**9.13**
राजस्व व्यय	**6.64**
पूंजीगत व्यय	**2.48**
पूंजीगत परिव्यय	**1.78**

राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है - सी.ए.जी (2023)

प्रमुख आर्थिक संकेतक

(₹ लाख करोड़ में)

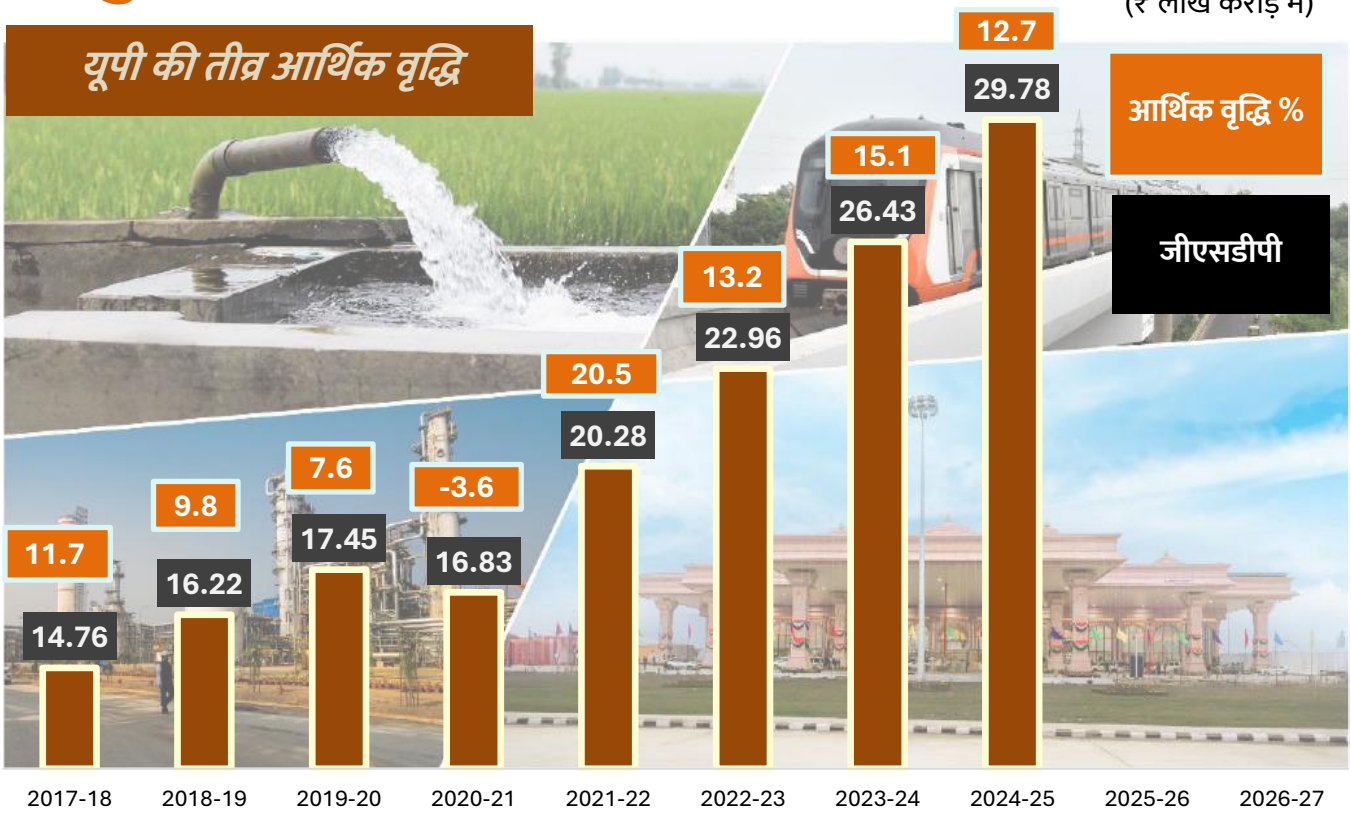

उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य

	₹ करोड़	जीएसडीपी का %
राजकोषीय घाटा (एफआरबीएम सीमा 3% है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा सुधारों के लिए 0.5% अतिरिक्त सीमा प्रदान की गयी, कुल सीमा 3.5%)	1,18,480.59	2.98
राजस्व अधिशेष (एफआरबीएम अधिनियम के मानकों के अनुसार अधिशेष बनाए रखा)	64,457.57	1.62
पूंजीगत परिव्यय	1,77,744.12	4.47
ऋणग्रस्तता	9,19,414.47	23.1

पूंजीगत व्यय में ₹1 लाख करोड़ से अधिक व्यय के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है।

निधि प्रवाह

निधि का अंतर्प्रवाह

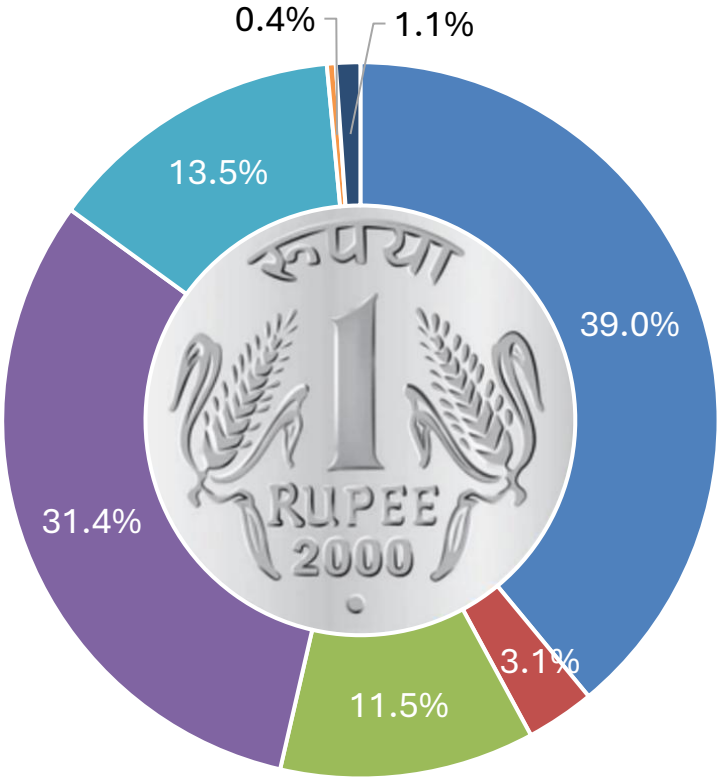

- स्वयं का कर राजस्व
- करेत्तर राजस्व
- केंद्र सरकार से सहायता अनुदान
- केन्द्रीय करों में राज्यांश
- लोक ऋण
- ऋण और अग्रिम की वसूली
- लोक लेखा ऋण

निधि का बहिर्प्रवाह

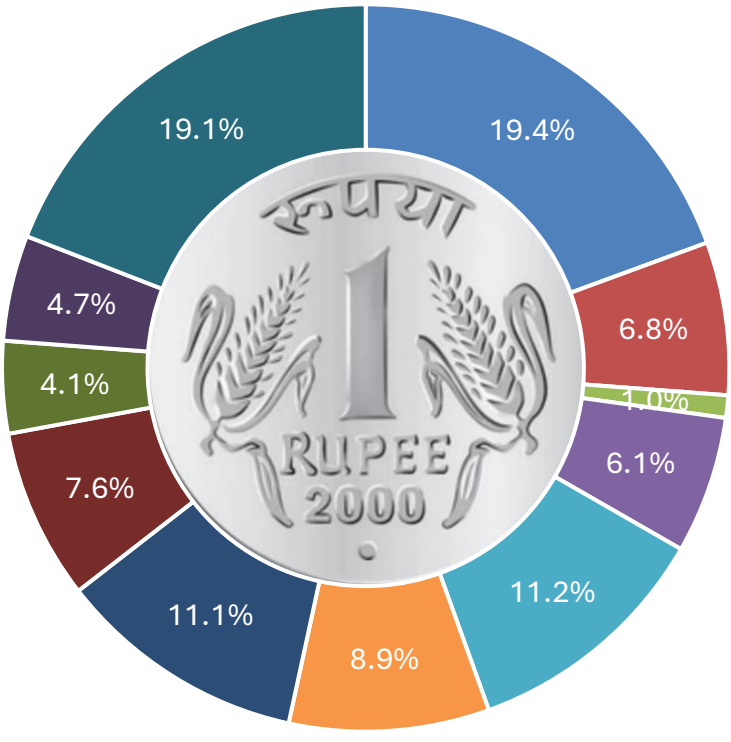

- पूंजीगत परिव्यय
- ऋणों का प्रतिदान
- ऋण एवं अग्रिम
- सहायता अनुदान
- वेतन–सरकारी कर्मचारी
- वेतन–सहायता प्राप्त संस्थाएं
- पेंशन
- ब्याज भुगतान
- स्थानीय निकायों को अंतरण
- सब्सिडी
- अन्य व्यय

राजस्व प्राप्तियां

प्रमुख उपलब्धियां

- राजस्व जुटाने में एआई का सक्रिय उपयोग
- ईओडीबी को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी जागरूकता अभियान
- भारत में प्रथम आबकारी निवेशक शिखर सम्मेलन
- भारत में पहली आबकारी निर्यात नीति
- एकमुश्त कर जमा सुविधा परिवहन विभाग

राजस्व स्रोत (₹ करोड़ में)

1	2	3	4
केंद्रीय करों में यूपी का अंश	केंद्र से सहायता अनुदान	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	राज्य का करेत्तर राजस्व
2,68,910.76	98,772	3,34,491	26,754

राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)

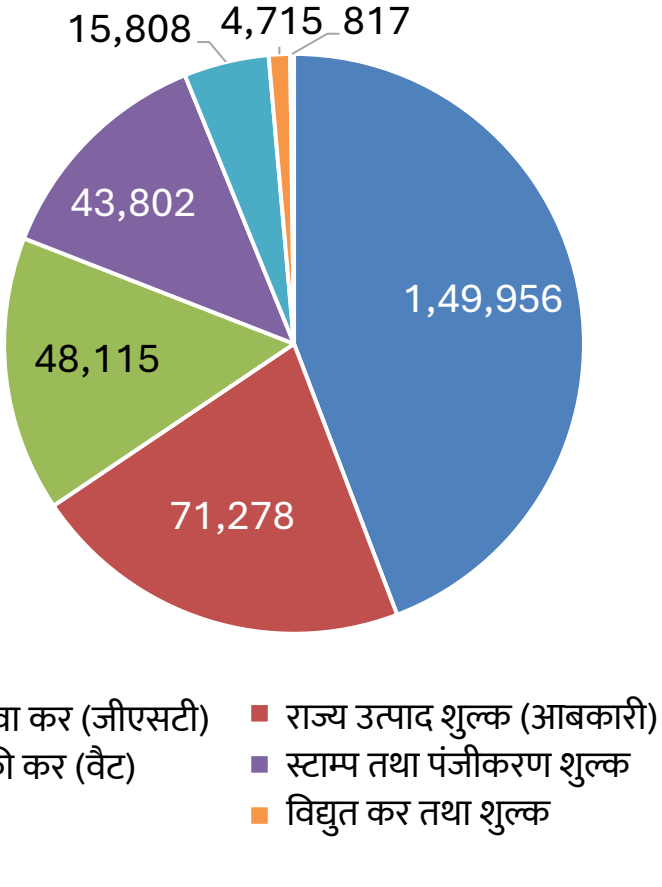

बजट व्यय

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत परिव्यय

2026-27

₹1,77,744 करोड़

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.47%

2017-18

₹39,088 करोड़
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.84%

राजस्व व्यय

प्रमुख घटक

वेतन
₹1,82,921 करोड़

पेंशन
₹1,01,901 करोड़

ब्याज भुगतान
₹68,921 करोड़

सब्सिडी
₹43,197 करोड़

विभागीय आवंटन

10 प्रमुख विभाग – समग्र बजट आवंटन	राशि (₹ करोड़ में)
1. शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	80,997.16
2. ऊर्जा	65,926.28
3. गृह (पुलिस)	44,145.77
4. लोक निर्माण	33,740.32
5. पंचायती राज	32,089.70
6. भारी एवं मध्यम उद्योग	27,103.49
7. ग्राम्य विकास	25,499.58
8. नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	22,675.80
9. चिकित्सा (परिवार कल्याण)	22,438.45
10. माध्यमिक शिक्षा	22,167.33

10 प्रमुख विभाग – पूंजीगत परिव्यय	राशि (₹ करोड़ में)
1. लोक निर्माण विभाग (सेतु एवं सड़कें)	29,369.71
2. नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	22,464.63
3. ऊर्जा	20,955.53
4. खाद्य तथा रसद	17,876. 77
5. ग्राम्य विकास	17,435. 22
6. भारी एवं मध्यम उद्योग	12,327.99
7. सिंचाई	11,942.93
8. शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	6,727.75
9. आवास	6,165.50
10. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	5,704.58

केन्द्रीय योजनाएं

1) पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क राशन
- खाद्य सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन का प्रमुख आधार

2) पीएम आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण)

- सभी के लिए घर
- ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान हेतु वित्तीय सहायता

3) जल जीवन मिशन

- प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से जल
- गुणवत्तापूर्ण जीवन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को बल

4) आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना

- प्रति वर्ष पात्र परिवारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
- गरीब एवं वंचित परिवारों को लाभ

5) पीएम किसान सम्मान निधि

- किसानों को प्रतिवर्ष ₹6 हजार की आर्थिक सहायता
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम

6) दीनदयाल अंत्योदय योजना

- स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों को सहायता
- महिला प्रधान स्वयं सहायता समूहों पर विशेष ध्यान

7) पीएम मुद्रा योजना

- सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बिना गारंटी ऋण
- युवा और महिला उद्यमियों को सहायता

8) स्किल इंडिया मिशन/पीएम कौशल विकास मिशन

- कौशल विकास एवं प्रमाणीकरण
- युवाओं को रोजगार के अवसर

9) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

- डिजिटल अवसंरचना, ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता
- एआई, फिनटेक और फ्यूचर-रेडी गवर्नेंस की आधारशिला

10) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना

- उत्पादन अभिवृद्धि के लिए मुख्य सेक्टर्स को प्रोत्साहन
- आर्थिक विकास एवं रोजगार के मुख्य संवाहक

11) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- संक्रामक/गैर-संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण
- आशा वर्कर एवं स्थानीय स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग की वृद्धि

12) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- विकेन्द्रीकृत योजना, उच्च तकनीकी मापदंड, त्रिस्तरीय गुणवत्ता परीक्षण व्यवस्था

राज्य की प्रमुख योजनाएं

		(₹ करोड़ में)
01	जल जीवन मिशन	15,060
02	अन्नपूर्ति योजना	15,480
03	प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (ग्रामीण + शहरी)	12,434
04	मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना	5,000
05	विकसित भारत जी-राम जी	5,544
06	अमृत 2.0	3,750
07	मुख्यमंत्री नवीन शहरी विस्तारीकरण योजना	3,500
08	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण + शहरी)	4,161
09	अटल औद्योगिक अवसंरचना मिशन	2,000
10	मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना	1,375
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	823
12	विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रोत्साहन नीति 2023	1,000
13	हवाई पट्टी निर्माण एवं विस्तारीकरण	1,100

नई योजनाएं

नगरीय विकास

- राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रबंधन, संचालन, सुरक्षा
- मेरठ, मथुरा-वृंदावन एवं कानपुर में अवसंरचना विकास
- सिटी इकॉनॉमिक रीजन

औद्योगिक विकास

- सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन
- एक जनपद-एक व्यंजन
- उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024
- उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022
- मुख्यमंत्री जीरो फैटेलिटी विजन योजना
- बस-बेड़ों का सुदृढ़ीकरण (ईवी)

कृषि एवं सहबद्ध

- किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फंड
- यूपी एग्रीज के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पादन विपणन योजना
- उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
- सहकारी चीनी मिलों में अवशेष गन्ना बकाया भुगतान
- मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी पशु चिकित्सालय कायाकल्प योजना
- प्रादेशिक पशुधन मिशन
- एक्वाब्रिज, एक्वाकल्चर आधारभूत संरचना
- उत्तर प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी

ऊर्जा

- यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के अंतर्गत परियोजनाएं एवं अनुसंधान
- डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना
- सोलर पार्क के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

नई योजनाएं

खेल एवं सहकारिता

- सहकारी समितियों के लिए नए गोदामों का निर्माण
- 10 मंडलों में खेल महाविद्यालयों की स्थापना
- मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ में नए भवन का निर्माण
- कानपुर में ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्विकास
- बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन हेतु वाहनों का क्रय
- माननीय सांसद/विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन

स्वास्थ्य सेवाएं

- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण
- फेज-1, 2, 3 के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सालय का निर्माण
- स्वशासी तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों मे ट्रॉमा सेंटर लेवल-2 का निर्माण
- पीपीपी मोड में चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन
- उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण नीति-2023 में सब्सिडी

शिक्षा एवं कौशल

- बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा
- नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का निर्माण
- सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब
- छात्राओं में सैनिटरी नैपकिन का वितरण
- मुख्यमंत्री भारतीय ज्ञान पद्धति ग्लोबल एक्सीलेंस फंड
- विज्ञान व तकनीकी विषयों में अध्ययनरत छात्राओं हेतु प्रत्येक जनपद में छात्रावास
- राज्य विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान हेतु फंड

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आईटी

- इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई डेटा लैब
- उत्तर प्रदेश स्टेट डेटा सेंटर
- लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर में U-HUB
- साइबर सुरक्षा संरक्षण केंद्र
- उत्तर प्रदेश एआई मिशन
- नए पॉलिटेक्निक का निर्माण व वर्तमान का उच्चीकरण
- टेक युवा-समर्थ युवा योजना
- उत्तर प्रदेश नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन
- उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर क्लस्टर
- आकाशीय विद्युत से बचाव, पूर्व चेतावनी हेतु सैटेलाइट पेलोड/सेंसर
- यूपी स्टेटवाइड एरिया नेटवर्क-3

नई योजनाएं

अवसंरचना विकास

- निरीक्षण गृहों व सर्किट हाउस का निर्माण, विस्तार व जीर्णोद्धार
- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण
- नगरीय सेतुओं का निर्माण
- रेलवे उपरिगामी, अधोगामी सेतुओं का निर्माण
- जनपदों, तहसील व विकासखण्डों में हेलीपैड निर्माण
- राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण
- धर्मार्थ मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण
- बाईपास/रिंग रोड, फ्लाईओवर का निर्माण
- लॉजिस्टिक पार्क हेतु सड़कों का निर्माण
- नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के लिए सड़कों का निर्माण
- नए विधानभवन का निर्माण
- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय
- बुंदेलखंड की विशेष परियजोनाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय

सामाजिक समता

- मुख्यमंत्री वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण
- दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राइसाइकिल
- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिसकर्मियों के लिए वाहनों का क्रय

अन्य

- त्वरित आर्थिक विकास योजना
- फ्यूचर-रेडी तहसीलों का निर्माण
- रानीपुर टाइगर रिजर्व फाउंडेशन कॉर्पस
- जीरो पॉवर्टी अभियान के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण
- जनगणना-2027 की तैयारी हेतु फंड
- यूपी-112 सेवा के लिए वाहनों का क्रय

उत्तर प्रदेश
उन्नति के नए शिखर पर...

अनथक यात्रा के 9 वर्ष

पिंक बजट

SHE-Marts (स्वयं सहायता उद्यमी हब)

- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में लॉन्च किया गया।
- SHE-Marts सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा केंद्र हैं जहां महिला उद्यमी अपने उत्पादों को सीधे बेच सकती हैं, ऋण-आधारित आजीविका के स्थान पर व्यवसाय की मालिक बन सकती हैं।
- यह कार्यक्रम 'लखपति दीदी' पहल की सफलता पर आधारित है और यह महिलाओं का तीन स्तरों यथा- बाजार, पूंजी और नेटवर्क पर सहयोग करता है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है तथा महिला समूहों को कृषि और गैर-कृषि दोनों बाजारों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

75000
महिलाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य

75
सभी जनपदों में

76547
महिलाएं प्रशिक्षित (मिशन शक्ति 1.0)

मिशन शक्ति (महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण)

- मिशन शक्ति, महिला सशक्तीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्यक्रम है
- यह महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, आत्मनिर्भरता, कानूनी जागरूकता और आर्थिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- मिशन शक्ति 5.0 का नया चरण 2025 में आरंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य में अधिक महिलाओं तक पहुंच, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा सामुदायिक सहयोग पर बल दिया गया।
- अभियान से महिलाओं की शिकायतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही, हेल्पलाइन और सामुदायिक केंद्रों को मजबूत किया गया है।

ग्रीन बजट

ग्रीन बजट टैगिंग | वित्तीय वर्ष 2026–27

ग्रीन बजट टैगिंग के मुख्य बिन्दु

- अनुकूलन, शमन और लचीलेपन के अंतर्गत वर्गीकृत
- UPSAPCC 2.0 के क्रियान्वयन में फंडिंग गैप
- प्रमुख, महत्वपूर्ण या अप्रत्यक्ष के अनुसार स्कीम टैगिंग
- विस्तारित सेक्टर कवरेज, योजना-स्तरीय जलवायु प्रासंगिकता स्कोरिंग

ग्रीन टैगिंग 58 से बढ़ाकर 60 विभागों में कर दी गई है, जिससे 11 सेक्टर में क्लाइमेट एलोकेशन 21% से बढ़कर 23.5 % हो गया है, अतः पूरे राज्य में जलवायु समन्वय में वृद्धि हुई है।

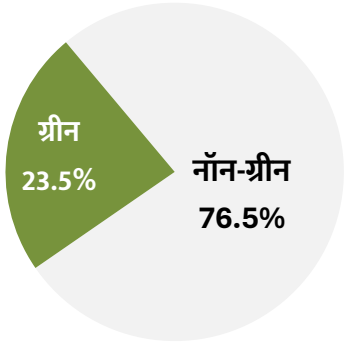

क्षेत्रवार कवरेज का विस्तार

01 स्थायी कृषि
UP-AGREES प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 28 जिलों में खेती को मॉडर्न बनाने तथा प्रोडक्टिविटी को 35% तक बढ़ाने के लिए डिज़ाइन

02 वन आवरण
242.13 करोड़ पेड़ लगाए गए। 3.38 लाख हेक्टेयर में वन की बढ़ोतरी

03 इलेक्ट्रिक वाहन
ई-बसों और वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में 40% बढ़ोतरी

04 नवीकरणीय ऊर्जा
1,038.27 MW (≈1.04 GW) सोलर कैपेसिटी; वाराणसी जनपद रूफटॉप सोलर में द्वितीय स्थान पर

05 स्वच्छ वायु प्रबंधन
विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम (UPCAMP) की स्वीकृति

06 उप-विधि और शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट उप-विधि 2025 लागू

07 अपशिष्ट प्रबंधन
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लखनऊ को तीसरा स्थान तथा प्रयागराज को स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर/सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में मान्यता

08 नीति और कार्य योजना
उत्तर प्रदेश राज्य हीट वेव एक्शन प्लान 2025 प्रकाशित एवं संचालित और अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी लॉन्च

09 बायो एनर्जी/सी.बी.जी. अभिवृद्धि:
यूपी में ~₹6,000 करोड़ के नए सी.बी.जी. प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी (मई 2025)

10 ग्रीन हाइड्रोजन
यूपी के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का गोरखपुर में उद्घाटन (टोरेंट पावर एवं टोरेंट गैस) तथा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लेंडिंग (2% तक ब्लेंडिंग की स्वीकृति)

सतत विकास

उत्तर प्रदेश : इंडेक्स स्कोर एसडीजी-वार [4.0]

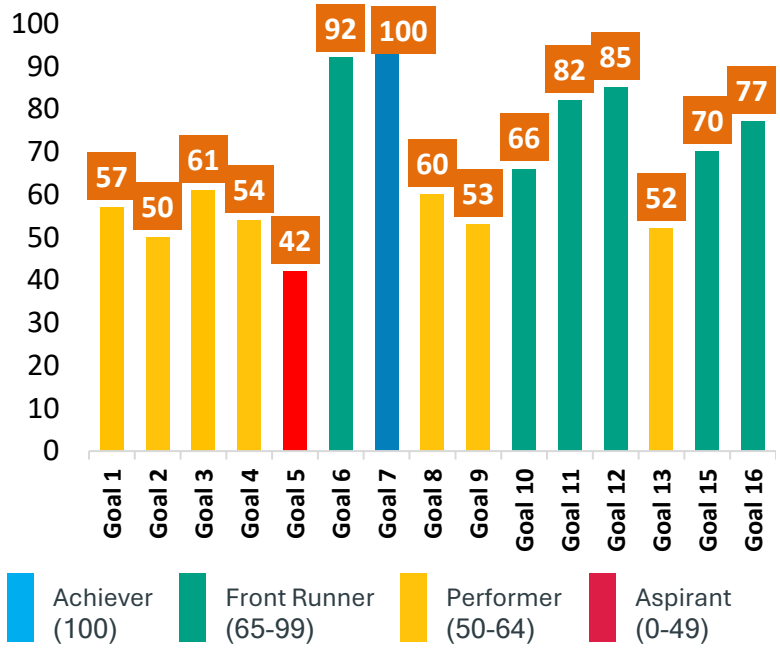

उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम (UPCAMP)

- परिवहन व्यवस्था, कृषि और उद्योग पर फोकस करने वाला $299.66 मिलियन का प्रोग्राम
- इसमें 39 लाख घरों के लिए क्लीन कुकिंग एक्सेस, ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को बदलना शामिल है।
- उत्तर प्रदेश द्वारा सीमा पार वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावी ढंग से और कम लागत में निपटने के लिए एक क्षेत्रीय, बहु-राज्य वायु क्षेत्र रणनीति अपनाई गयी है।

उत्तर प्रदेश CCUS स्कीम 2026

कम कार्बन वाले औद्योगिक भविष्य की ओर

राष्ट्रीय संदर्भ

- 'पंचामृत' के अंतर्गत 2070 तक **नेट-जीरो** का लक्ष्य
- केंद्रीय बजट 2026-27: **CCUS के लिए ₹20,000 करोड़**
- **पावर, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, केमिकल्स** सेक्टर्स पर फोकस

उत्तर प्रदेश के लिए CCUS क्यों?

- हाई प्रोसेस-बेस्ड कार्बन उत्सर्जन यथा: थर्मल पावर, सीमेंट, उर्वरक
- कार्बन उत्सर्जन को केवल नवीकरणीय ऊर्जा से समाप्त नहीं किया जा सकता
- नेशनल CCUS पॉलिसी इस चुनौती को हाईलाइट करती है
- CCTS 2023 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए मजबूत MRV सिस्टम की जरूरत है

उत्तर प्रदेश CCUS स्कीम 2026- मुख्य घटक

- मिशन मोड पायलट प्रोजेक्ट्स-ऊर्जा, सीमेंट स्टील, उर्वरक, कृषि कृषि, वेस्ट, केमिकल्स
- बड़े औद्योगिक हब में क्लस्टर-आधारित कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर
- निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन

सूर्य मित्र उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा दृष्टिकोण का अभिन्न अंग हैं-वे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में सहयोग करते हैं, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं और रोजगार सृजन में योगदान देते हैं।

3.5 लाख से अधिक रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जो बड़े पैमाने पर हरित ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, बिजली के बिलों में 60-90% की कटौती कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश दैनिक रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

रूफटॉप सौर ऊर्जा में नेतृत्व: उत्तर प्रदेश ने 1 GW का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 2.9 लाख घरों तक पहुंच गई है।

उत्तर प्रदेश : एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

उत्तर प्रदेश के लिए विकास रणनीति कृषि, उद्योग, पर्यटन और IT/ITes जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इस रणनीति का उद्देश्य व्यापार और विनिर्माण में विविधता लाने के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा और टेक्नोलॉजी अपनाने को बढ़ावा देना है। मुख्य सेक्टर की प्रगति प्रमुख क्षेत्रों यथा ऊर्जा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और स्वास्थ्य आदि के परस्पर विकास पर निर्भर करती है।

विकास संवाहक

1. विनिर्माण क्षेत्र में विकास
2. वेल्यू चेन दक्षता
3. तकनीक-आधारित विकास
4. संतुलित क्षेत्रीय विकास
5. निवेश आकर्षित करना
6. स्टार्ट-अप और नवाचार

मूल संवाहक

कृषि
नवाचार की शक्ति का दोहन: उत्तर प्रदेश में भविष्य में हाइटेक कृषि

उत्पादन
30प्र0 में मैन्युफैक्चरिंग क्रांति को गति देना

पर्यटन
पर्यटन को बढ़ावा देना एवं नये पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर अवसंरचना विकास

IT और ITes
डिजिटल युग को बढ़ावा देना

इनेबलिंग सेक्टर

ऊर्जा:
सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना

अवसंरचना:
सतत आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करना

शिक्षा और कौशल:
शैक्षिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता के माध्यम से विकास को सशक्त बनाना

नगर:
भविष्य के लिए शहरों का निर्माण

स्वास्थ्य:
सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिससे जीवन का स्तर बेहतर हो सके

भारत का पसंदीदा व्यावसायिक गंतव्य

प्रथम
जीएसटी पंजीकरण में

1.42 करोड़
हवाई यात्री (FY24-25)

द्वितीय
एमएसएमई पंजीकरण (10 फरवरी, 2026 तक)

16,000+
DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

अनुकूल नीति परिवेश

StartInUP: उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल; उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स। 1,888+ स्टार्टइनयूपी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप।

PLEDGE Park: 12 पार्कों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 6 स्थानों पर भूखंड आवंटन शुरू किया गया है, जो कुल 136 एकड़ क्षेत्र में स्थित है।

फिल्म सिटी : सेक्टर – 21 में 230 एकड़ भूमि पर पीपीपी परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त, 1,510 एकड़ भूमि का आवंटन भी पूरा हो गया है

सुगम्य व्यापार विधेयक (2025): 13 राज्य अधिनियमों की 99% आपराधिक धाराओं को अपराध मुक्त किया गया और निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत की गयी।

उपलब्धियां

- ✓ नीति आयोग के Export Preparedness Index 2024 में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है।
- ✓ **18,568 स्टार्टअप** वर्तमान में सक्रिय हैं (दिसंबर 2025 तक) जिनमें से लगभग 8,000 का नेतृत्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में **8 यूनिकॉर्न** हैं तथा 2030 तक 20 यूनिकॉर्न बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- ✓ यूपीसीडा द्वारा 2024-25 में 798 आवंटनों के साथ **अब तक का सबसे अधिक भूमि आवंटन** दर्ज किया गया, जिससे ₹60,000 करोड़+ के निवेश आकर्षित हुए और 52,000+ रोजगार सृजित हुए।
- ✓ 33 क्षेत्रीय नीतियों, निवेश सारथी पोर्टल, पिछले 8 वर्षों में ₹15 लाख करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में **Achiever State** की उपलब्धि प्राप्त की है।
- ✓ GCC Policy (2025 से लागू): प्रोत्साहन, सब्सिडी, पूंजी और परिचालन सहायता।

उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा

16
हवाई अड्डे संचालित

7
एक्सप्रेसवे संचालित (15 विकास के विभिन्न चरणों में)

6
शहरों में मेट्रो संचालित

36,741 मेगावॉट
स्थापित ऊर्जा क्षमता (31 दिसम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार)

परिवर्तनकारी पहल

नोएडा में जेवर हवाई अड्डे (DXN) का उद्घाटन शीघ्र प्रस्तावित है; 62 घरेलू, 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ परिचालन आरम्भ किया जायेगा।

एक्सप्रेस-वे लीडर: उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक कनेक्टेड राज्य के रूप में उभरा है और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60% हिस्सा यूपी में है।

सेतु बंधन: इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी CRIF फंडिंग के अंतर्गत 1,111 करोड़ रुपये से दस प्रमुख पुलों का निर्माण करेगा।

राज्य: क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS-UDAN) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने हवाई संपर्क के विस्तार हेतु किये गये तीव्र प्रयासों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है।

लॉजिस्टिक क्लस्टर: UPEIDA द्वारा 5 एक्सप्रेसवे के साथ-साथ रणनीतिक रूप से स्थित 27 UPIMLCs का विकास किया जा रहा है। जिससे कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम

डिजिटल लेनदेन 2017-18 में 122.84 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 1,380.91 करोड़ हो गए।

एआई शहर: एआई अवसंरचना के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

जून 2025 तक ₹21,343 करोड़ (2.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निवेश के साथ 644 मेगावाट की प्रस्तावित डेटा सेंटर क्षमता प्राप्त कर ली गई है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई, जिसमें निवेशकों के लिए बड़े प्रोत्साहन के साथ 2030 तक 50 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश एआई मिशन (UP-AIM)

UP-AIM का उद्देश्य शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में एआई को अपनाने में तेजी लाना है

UP-AIM के मुख्य स्तंभ

स्तंभ 1: एआई कम्प्यूटिंग एवं अवसंरचना तक पहुंच

स्तंभ 2: ओपन डेटा और डेटासेट प्लेटफॉर्म

स्तंभ 3: आधारभूत मॉडल का प्रभावी उपयोग

स्तंभ 4: विभिन्न क्षेत्रों में एआई उपयोग के सन्दर्भ को अपनाना

स्तंभ 5: क्षमता और कौशल निर्माण

स्तंभ 6: स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम

स्तंभ 7: उत्कृष्टता और अनुसंधान केंद्र

स्तंभ 8: सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई

पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार

#1
भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या

3x
2016 से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

12+
विविध पर्यटक सर्किट

3
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

महाकुंभ 2025

- 4,000 हेक्टेयर+ क्षेत्र में फैले एक अस्थायी शहर का विकास।
- 450 किलोमीटर लंबी आंतरिक सड़कों, स्वच्छता प्रणालियों, चिकित्सा क्षेत्रों और निगरानी नेटवर्क का निर्माण।
- विश्व स्तर पर सबसे बड़ा जनसमूह, 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में दीये जलाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
- लखनऊ को यूनेस्को द्वारा 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी' नामित किया गया।
- सोनभद्र में स्थित सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है।

पर्यटन विकास हेतु प्रमुख पहल

50,000 नए होमस्टे, ब्याज सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट, एस.जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति एवं अन्य प्रोत्साहन।

मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना हेतु पर्याप्त धन आवंटन

40 वर्ष तक के युवा स्नातकों को पर्यटन स्थलों पर शोध करने, प्रचार करने और पर्यवेक्षण करने के लिए 40,000 रुपये प्रति माह की सहायता

उत्तर प्रदेश को ग्रामीण पर्यटन राजधानी बनाने के लिए 234 गांव पर्यटन केंद्र के रूप में चिन्हित

सामाजिक उपलब्धियां

सीएम युवा : उद्योग/सेवा क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक/सेवा परियोजनाओं पर ₹5 लाख तक के ब्याज मुक्त और बिना गारंटी वाले ऋण, साथ ही परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी सब्सिडी हेतु प्रावधान।

मार्च 2017 में राज्य का कुल बैंकिंग कारोबार ₹12.80 लाख करोड़ था, जो दिसंबर 2025 में बढ़कर ₹32.79 लाख करोड़ हो गया है।

पिछले वर्ष एमएसएमई दिवस, मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन, विश्वकर्मा जयंती, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और यूपी दिवस जैसे कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर ऋण वितरण किया गया है।

दिसंबर 2025 तक, राज्य में कुल 4,30,565 बैंकिंग आउटलेट सक्रिय हैं, जिनमें 20,913 शाखाएं, 19,191 एटीएम और 4.09 लाख बैंक मित्र और बीसी सखी शामिल हैं।

57,699 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए, 22.24 लाख जन धन खाते खोले गए, 17.14 लाख लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में और 43.35 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में नामांकित किया गया।

दिसंबर 2025 तक 50.82 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ₹1 लाख करोड़ से अधिक की लिमिट स्वीकृत की गई है।

सामाजिक उपलब्धियां

राज्य सरकार ने फार्मा अनुसंधान और नवाचार के लिए धारा-8 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था 'प्रमोट फार्मा' ₹500 करोड़ के परिक्रामी कोष (Revolving Fund) के अंतर्गत स्थापित की है।
उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस उद्योग नीति 2023 में पूंजीगत सब्सिडी (25% तक), बुनियादी ढांचे/भूमि के लिए 50-60% ब्याज सब्सिडी और 100% स्टांप शुल्क छूट का प्रावधान है।

राज्य ने 7,409 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और 5,228 स्कूलों में Technology Labs के लिए Resource Centre स्थापित किए हैं, जिससे आधुनिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार हुआ है।

वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जिनमें स्वायत्त, सरकारी, केंद्रीय और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में 7,350 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।

2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए, नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ₹5.73 लाख करोड़ के ऋण प्रवाह का अनुमान लगाया है। दिसंबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश 60.39 के CD ratio के साथ देश में अग्रणी है।

150 सरकारी ITI में AI-ML पाठ्यक्रम शुरू किया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत 11 नए ट्रेंड शामिल किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में 5 CIITT Centres स्थापित किए जा रहे हैं, जहां नई तकनीकों का परीक्षण दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश : जन सेवा में अग्रणी

		योजना	मीट्रिक	अब तक
#1	PMJDY	पीएमजेडीवाई	खातों की संख्या	10.13 करोड़
#1	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	पीएमएसबीवाई	खातों की संख्या	7.94 करोड़
#1	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana	पीएमजेजेबीवाई	खातों की संख्या	2.92 करोड़
#1	Atal Pension Yojana	अटल पेंशन योजना (APY)	खातों की संख्या	1.37 करोड़
#1	PM SVANidhi योजना रेहड़ी-पटरी वालों का स्वाभिमान	पीएम-स्वनिधि	खातों की संख्या	21.35 लाख (₹3149.73 करोड़)

अन्य मुख्य योजनाएं (2025-26)

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना | लाभार्थी — 35 लाख (₹43,689 करोड़ वितरित)
2. मुख्यमंत्री युवा योजना | लाभार्थी — 1.10 लाख
3. आयुष्मान भारत दावा धनराशि का भुगतान — ₹3,341 करोड़ (देश में प्रथम)
4. डिजिटल ट्रांसक्शन नं. दिसंबर 2025 — 1635.72 (₹191.60 लाख करोड़)

“यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 9 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुने से अधिक हो चुकी है। हम देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं।”

- सुरेश कुमार खन्ना

मंत्री, वित्त एवं संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश
एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर

सौजन्य :

वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण: यह पुस्तिका बजट का सार है। कृपया विस्तृत विवरण के लिए आधिकारिक दस्तावेज देखे।